दैनिक जागरण
प्रकृति हमारी सबसे करीबी मित्र है

# मकसद ही है हंगामा

महज दो दिनों में लोकसभा से 45 सांसदों का निलंबन यही बता रहा है कि सांसद किस तरह हंगामा करने पर आमादा रहने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को जिस तरह लगातार दूसरे दिन हंगामा करके सदन की कार्यवाही बाधित करने वाले सांसदों को निलंबित करना पड़ा उससे यह भी पता चल रहा कि वे उनकी सख्ती से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। हैरानी नहीं कि निलंबित सांसद अपनी गलती पर विचार करने और अपने आचरण में सुधार लाने के बजाय इसकी शिकायत करते दिखें कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आखिर यह किसी से छिपा नहीं कि इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ने जब हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित किया था तो उनके बचाव में कई अन्य सांसद खड़े हो गए थे। जाहिर है इससे हंगामा करने वाले सांसदों को बल ही मिला। निःसंदेह सांसदों को निलंबित करना समस्या का हल नहीं, लेकिन यह भी ठीक नहीं कि उन्हें संसद की कार्यवाही ठप करने की खुली छूट दे दी जाए। यह संसदीय गरिमा के सर्वथा प्रतिकूल है कि सांसद सदन में बहस करने के बजाय नारे लिखी तख्तियां लहराने का काम करें। दुर्भाग्य से अब ऐसा ही अधिक होता है। विगत दिवस ही राफेल सौदे पर चर्चा के दौरान कुछ कांग्रेसी सांसद कागज के जहाज बनाकर उड़ाने में लगे हुए थे। ऐसा बचकाना व्यवहार तो संसद की गरिमा से खुला खिलवाड़ ही है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सांसदों का एक वर्ग यह मान बैठा है कि उसका प्राथमिक काम संसद में नारे लगाना और शोर मचाना है। वे सवाल पूछने और चर्चा करने से ज्यादा दिलचस्पी नारे लिखी तख्तियां तैयार करने में दिखाने लगे हैं। उनकी कोशिश यह भी रहती है कि नारे लिखी ये तख्तियां टीवी कैमरों में कैद हो जाएं।

माना यह गया था कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सांसदों को संसदीय कामकाज के प्रति और संजीदा बनाएगा, लेकिन अब ठीक इसका उलटा दिखने लगा है। बेहतर हो कि इस पर विचार हो कि सीधा प्रसारण संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहायक बन रहा है या सिरदर्द? बीते कुछ समय से सांसद सदनों के अंदर काम करने से ज्यादा संसद परिसर में धरना-प्रदर्शन की मुद्रा में भी दिखने लगे हैं। अगर संसद जाकर सड़क की राजनीति करनी है तो फिर वहां हाजिरी देने का मतलब ही क्या है? संसद में काम कम और हंगामा अधिक होने के लिए जितने जिम्मेदार सांसद हैं उससे अधिक राजनीतिक दलों का नेतृत्व। आम तौर पर अपने नेता और नेतृत्व के इशारे पर ही सांसद हंगामा करते हैं। एक समस्या यह भी है कि संसद में अपने दायित्वों का सही तरह निर्वाह करने वाले सांसदों से अधिक चर्चा उन्हें मिलने लगी है जो येन-केन-प्रकारेण सदन की कार्यवाही में खलल डालते हैं। संसद सत्तापक्ष और विपक्ष के समन्वय एवं ज्वलंत मसलों पर सार्थक बहस के प्रति दिलचस्पी से ही चल सकती है, निरर्थक सर्वदलीय बैठकों से नहीं। बेहतर हो कि सभी दल गंभीरता से विचार करें कि इस स्थिति का निर्माण कैसे हो। अगर संसद में इसी तरह हंगामा होता रहा तो उसकी महत्ता कायम रहना कठिन है।

# शहरी विकास मॉडल

समय के साथ हर शहर के विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। झारखंड में नगर के भीतर एक नया नगर बसाने की कवायद अलग-अलग तरीके से की भी जा रही है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर के भी विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए सरकार के समक्ष ग्रेटर जमशेदपुर या न्यू जमशेदपुर बसाने का प्रस्ताव प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा की ओर से दिया गया है। देश में निजी क्षेत्र में बसाए गए पहले नियोजित शहर के रूप में जमशेदपुर की वैश्विक पहचान है। इसके नामकरण के सौ साल इसी दो जनवरी को पूरे हुए। जमशेदपुर का एक सौ साल का सफरनामा शहरी विकास में रुचि रखने वालों के लिए किसी केस स्टडी से कम नहीं है। सौ साल के हो चुके जमशेदपुर में यदि अगले सौ साल की आवश्यकताओं के लिए सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त रखा जा सकता है, साफ-सफाई सही तरीके से की जा सकती है, पार्क-मैदान का विस्तार किया जा सकता है, हरियाली को कायम रखते हुए शहर को सुंदर बनाने की योजना को प्रभावी तरीके से अमल में लाया जा सकता है तो यह कहा ही जा सकता कि शहरी विकास के जमशेदपुर मॉडल में बहुत दम है। इसलिए रांची, धनबाद, हजारीबाग समेत राज्य के अन्य शहरों के विकास की योजनाओं को बनाने या उन्हें लागू कराने के वक्त सरकार को इस जमशेदपुर मॉडल पर गौर करना चाहिए। इसके लिए बकायदा एक तंत्र विकसित किया जाए। विशेषज्ञों की एक टीम बने जो इस मॉडल का गहराई के अध्ययन कर आज के परिवेश में एक ऐसा मॉडल तैयार करे जो पूरे झारखंड के शहरी विकास पर एकसमान तरीके से लागू हो। ऐसा करने से अनियोजित तरीके से नगर-मोहल्ले को बसाने से उत्पन्न होने वाली कई तरह की परेशानियों से निजात मिल सकेगी। भ्रष्टाचार और अवैध कमाई के बड़े जरिये को भी खत्म किया जा सकेगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में शासन-प्रशासन को सहूलियत रहेगी। इसे विकास के नए मानक के रूप में निरुपित किया जा सकेगा। दूसरे राज्यों के सामने झारखंड नजीर पेश कर सकेगा। तो फिर देर किस बात की?

# राष्ट्रीय आकांक्षा है राम मंदिर का निर्माण

**मनमोहन वैद्य**

### सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राष्ट्रीय दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है डॉ. राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ मंदिर में दिया गया भाषण

प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु ज्योतिर्लिंग की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपनी स्वीकृति दी थी और वह 11 मई, 1951 को वहां गए भी। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही भारत के सांस्कृतिक गौरव चिन्हों को पुनर्स्थापित करना और करोड़ों लोगों की श्रद्धा के ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर राष्ट्रीय दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण डॉ. राजेंद्र प्रसाद का उक्त अवसर पर दिया गया भाषण है। महात्मा गांधी जी के 'रामराज्य' का स्वप्न जिन राजा रामचंद्र के कारण था उनकी जन्मस्थली पर उनके मंदिर को ध्वस्त करने के अपमान को निरस्त कर उनका भव्य मंदिर वहीं बनाने के संकल्प को राष्ट्रीय दृष्टि से कैसे देखना चाहिए, यह भी उनके भाषण से स्पष्ट होता है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भाषण इस प्रकार था-

''हमारे शास्त्र में श्री सोमनाथ जी को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है और इसलिए पुरातन काल में भारत की समृद्धि, श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक भगवान सोमनाथ का यह मंदिर था। दूर-दूर तक और देश-देश में इसके अतुलनीय वैभव की ख्याति फैली हुई थी, किंतु जातीय श्रद्धा का बाह्य प्रतीक चाहे विध्वंस किया जा सके पर उसका स्रोत तो कभी नहीं टूट सकता। यही कारण है कि सब विपत्तियां पड़ने पर भी भारत के लोगों के हृदय में भगवान सोमनाथ के इस मंदिर के प्रति श्रद्धा बनी रही और उनका यह स्वप्न बराबर रहा कि वे इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पुनः कर दें। समय-समय पर वे ऐसा करते भी रहे और आज ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार के पश्चात इसके प्रांगण में भारत के कोने-कोने से आए हुए अनेक नर-नारियों का कलरव फिर सुनवाई दे रहा है। ...सोमनाथ का यह मंदिर आज फिर अपना मस्तक ऊंचा कर संसार के सामने यह घोषित कर रहा है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिसके लिए जनता के हृदय में अक्षय श्रद्धा और स्नेह है उसे संसार में कोई भी मिटा नहीं सकता। आज इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा पुनः हो रही है और जब तक इसका आधार जनता के हृदय में बना रहेगा तब तक यह मंदिर अमर रहेगा।... इस पुनीत, पावन, ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके लिए यह उचित है कि हम धर्म के इस महान तत्व को समझ लें कि भगवान की सत्य की झांकी पाने के लिए कोई एक ही मार्ग मनुष्य के लिए अनिवार्य नहीं है। दुर्भाग्यवश धर्म और जीवन के इस तथ्य को विभिन्न युगों और विभिन्न जातियों में ठीक-ठीक नहीं अपनाया गया और इसी कारण धर्म के नाम पर संसार के विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों में अत्यंत विनाशकारी और बीभत्स संघर्ष और युद्ध हुए। धार्मिक असहिष्णुता से सिवाय विद्वेष और अनाचार बढ़ने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता। यही इतिहास की शिक्षा है और इसे हम सबको गांठ बांध रखना चाहिए। इस बात की आज विशेष आवश्यकता है कि हममें से प्रत्येक यह समझ ले कि हमारे देश में जितने संप्रदाय और समुदाय हैं उन सबके प्रति हमें समता और आदर का व्यवहार करना है। ऐसा करने में ही हमारी सारी जाति और देश का तथा प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण निहित है। इसी विश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे भारतीय संघ ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई है और इसका आश्वासन दिया है कि देश में बसने वाले प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को राज्य की ओर से एक समान सुविधाएं प्राप्त होंगी।...इस पुनीत अवसर पर हम सबके लिए यह उचित है कि हम आज इस बात का व्रत लें कि जिस प्रकार हमने आज अपनी ऐतिहासिक श्रद्धा के इस प्रतीक में फिर से प्राण-प्रतिष्ठा की है उसी प्रकार हम देश के जन साधारण के उस समृद्ध मंदिर में भी प्राण-प्रतिष्ठा पूरी लगन से करेंगे जिसका एक चिन्ह सोमनाथ का पुरातन मंदिर था। उस ऐतिहासिक काल में हमारा देश जगत का औद्योगिक केंद्र था। यहां के बने हुए माल से लदे कारवां दूर-दूर देशों को जाते थे और संसार का चांदी-सोना इस देश में अत्यधिक मात्रा में खिंचा चला आता था। हमारा निर्यात उस युग में बहुत था और आयात बहुत कम। इसलिए भारत उस युग में स्वर्ण और चांदी का भंडार बना हुआ था। आज जिस प्रकार समृद्ध देशों के तहखाने में संसार का स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में पड़ा रहता है उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व देश में संसार के स्वर्ण का अधिक भाग हमारे देवस्थानों में होता था। मैं समझता हूं कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण उसी दिन पूरा होगा जिस दिन न केवल इस प्रस्तर की बुनियाद पर भव्य भवन खड़ा हो गया होगा, वरन भारत की उस समृद्धि का भी भवन तैयार हो गया होगा जिसका प्रतीक पुरातन सोमनाथ का मंदिर था। इसके साथ ही मेरी समझ से सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक भी पूरा नहीं होगा जब तक कि इस देश की संस्कृति का स्तर इतना ऊंचा न हो जाए कि यदि कोई वर्तमान अलबरूनी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे तो हमारी संस्कृति के बारे में आज की दुनिया में वही भाव प्रकट करे। नव निर्माण का यह यज्ञ स्वर्गीय बल्लभ भाई पटेल ने आरंभ किया था। भारत की विच्छिन्नता को पुनः एक और अखंड करने में उनका निर्णायक हाथ था। उनके हृदय में यह आकांक्षा उत्पन्न हुई थी कि नव निर्माण के प्रतीक स्वरूप भारत की पुरातन श्रद्धा का यह प्रतीक फिर से निर्मित किया जाए। वह स्वप्न भगवान की कृपा से आज एक सीमा तक पूरा हो गया, किंतु वह पूर्णरूपेण उसी समय पूरा हो सकेगा जब भारत के जनजीवन का वैसा ही सुंदर मंदिर बन गया होगा जैसा यह मंदिर है। जय भारत।''

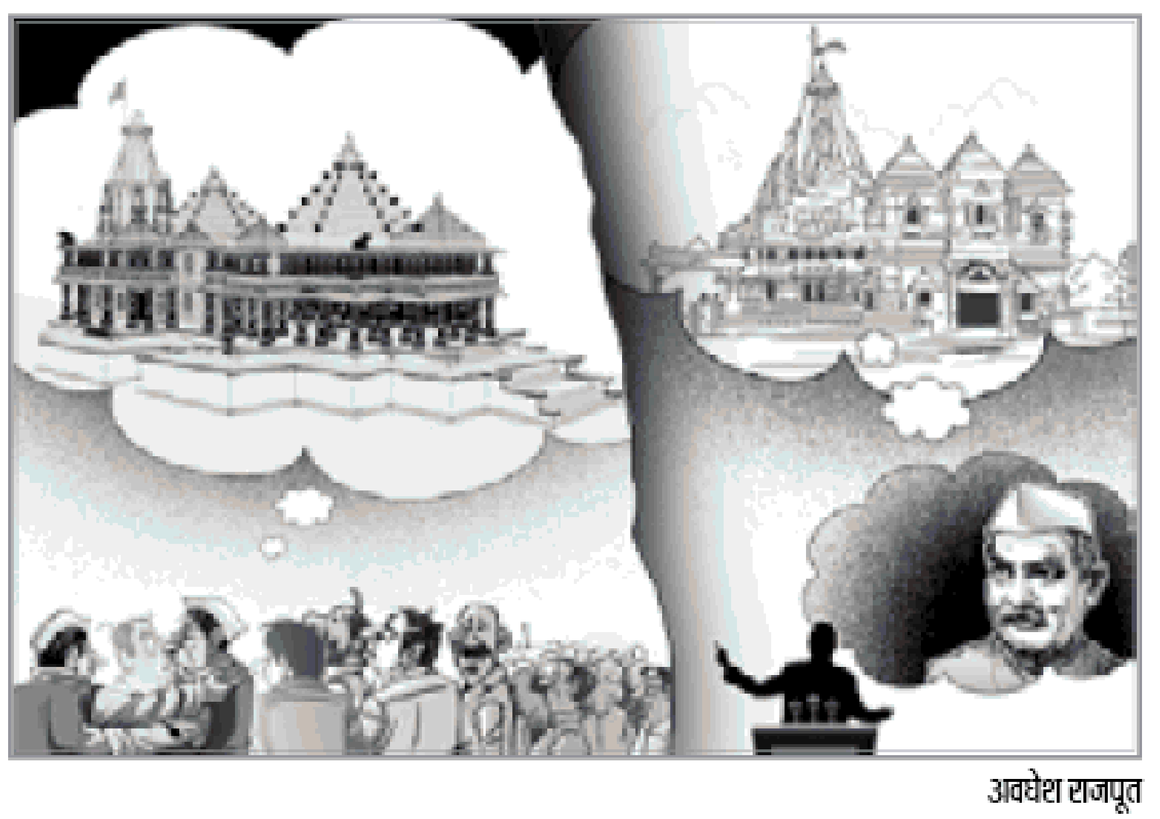

अवधेश राजपूत

आखिर इस भाषण में ऐसा आपत्तिजनक क्या था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको सरकारी रिकॉर्ड में नहीं लेने दिया। यह भारतीय अवधारणा और अभारतीय अवधारणा के बीच संघर्ष का उदाहरण है। आजादी के साथ ही भारत के वामपंथी नेहरूजी की आड़ में इस अभारतीय अवधारणा को समाज और जीवन के हर क्षेत्र में थोपने का प्रयास करते रहे। इस कारण भारत का 'भारतत्व' पूर्ण पुरुषार्थ के साथ प्रकट नहीं हो सका।

करोड़ों (हिंदू और मुस्लिम) भारतीयों की अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनाने की राष्ट्रीय आकांक्षा का कुछ लोगों द्वारा विरोध भी इन दो अवधारणाओं के बीच का संघर्ष ही है। सोमनाथ के मंदिर को भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक गौरव से जोड़ना और साथ ही यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि वैसी ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के साथ मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होगा। इसी तरह भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र के साथ गांधी जी की 'रामराज्य' की कल्पना को साकार करने के संकल्प को पूरा करने के साथ अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण को जोड़ना भारत के गौरव के साथ भारत का पुरुषार्थ प्रकट होने में सहायक होगा।

यह भी ध्यान रहे कि 1528 में मुगल आक्रमणकारी बाबर के लिए अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना आवश्यक नहीं था। मस्जिद बनानी भी थी तो वह अन्य कहीं पर भी बन सकती थी। अब तो इस्लामिक स्कॉलर्स भी यह कहते हैं कि बाबर के वजीर का कृत्य न तो इस्लामिक था न ही धार्मिक। उसे तो केवल हिंदुओं का अपमान करना था।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह हैं)

response@jagran.com

# वक्त की मांग है यूनिवर्सल बेसिक इनकम

**डॉ. विकास सिंह**

कई शोध पुष्ट करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम उस दुष्चक्र से मुक्ति दिलाती है जहां किसी देश की आर्थिक ऊर्जा कैद होती है

गरीबी के खिलाफ जंग और खासकर किसानों की बदहाली दूर करने के सिलसिले में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम फिर चर्चा के केंद्र में है। कुछ लोग इसे बौद्धिक जुगाली ही समझते हैं, लेकिन उन्हें इसका गणित समझने की जरूरत है। यह राजनीतिक आजादी से आगे की राह खोलती है जिसके माध्यम से ही आर्थिक आजादी संभव होगी। नीति निर्धारक अक्सर आंकड़ों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने की राह में खड़ा कर देते हैं। यहां यह भी सोचना होगा कि जो पैसा सरकार लोकलुभावन योजनाओं पर खर्च करती है और जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी होता है उससे अर्थव्यवस्था समावेशी और गतिशील बनने के बजाय अकुशल और शोषक बन जाती है। साथ ही आर्थिक खुशहाली का आंनद उठा रहे लोग हाशिए पर रहने वाले लोगों की परेशानियों से बेपरवाह रहते हैं। जैसे पर्यावरण हमारी साझी विरासत और जिम्मेदारी है वैसे ही एक स्वस्थ एवं समावेशी अर्थव्यवस्था भी हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी ने गरीबी को लेकर दुरुस्त ही कहा है कि 'पावर्टी एनिव्हेयर इज ए थ्रेट टू एवरीव्हेयर' यानी किसी भी जगह की गरीबी हर जगह के लिए खतरा है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के अनुसार दुनिया के वंचित लोगों में से लगभग 45 फीसद भारत में रहते हैं। यहां गरीबी एकआयामी नहीं, बल्कि बहुआयामी समस्या है। सवाल यह नहीं कि वृद्धि कितनी तेज गति से हो रही है, बल्कि यह है कि इसकी दिशा क्या है? इसकी धारा किन लोगों को गरीबी के चंगुल से छुड़ाकर सशक्त बना रही है? मानव विकास रिपोर्ट में हम 131 वें पायदान पर हैं जिससे पुष्टि होती है हम कहीं अपना रास्ता भूल रहे हैं। हमें अपनी दिशा सुधारने की जरूरत है। यहां लक्ष्य के स्तर पर सरकार की समावेशी विकास की नीति सराहनीय है, मगर सवाल उस रास्ते का है जिस पर चलकर हमें यह मंजिल हासिल होगी। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं इस मामले में कहीं न कहीं मात खा गई हैं और अब हमें नई राह तलाशनी होगी। आर्थिक मोर्चे पर गरीबी के कारण और परिणाम, दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। इससे एक दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलने के लिए कोशिश और ताकत की जरूरत होती है। जब हम समृद्धि पर नजर डालते हैं तो उसकी पिरामिड संरचना हमें शर्मसार करती है। इसने बहुआयामी असमानता को जन्म दिया है जिसने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हर मोर्चे पर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। इसकी ताकत असमानता के आकार पर निर्भर है। पिछले 50 सालों में विकास के आंकड़े दर्शाते हैं कि आय में असमानता की बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को कम करती है। भारत में गरीबों के लिए

कल्याणकारी योजना के नाम पर लगभग सौ योजनाएं हैं जिन पर हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसद खर्च करते हैं। थोड़ी राजनीतिक हिम्मत दिखाकर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू कर सकते हैं। दुनिया भर में किए गए शोध इसे पुष्ट करते हैं कि यह हमें उस फांस से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी जहां हमारी आर्थिक ऊर्जा कैद है। यह हमें एक साथ कई मोर्चे पर मदद कर सकती है। बेहतर बचत, बेहतर निवेश, आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास।

समावेशी विकास की बात आते ही भारत में सबसे पहले किसानों के विकास की बात होती है। बहुसंख्यक और गरीब होने की वजह से यह भारत में एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। पिछले 70 सालों के प्रयासों का कोई खास नतीजा नहीं निकला है। अभी भी किसान आत्महत्या को मजबूर होते हैं और किसानों की कर्ज माफी पर ही आज सबसे अधिक चर्चा हो रही है यानी किसानों के कल्याण को लेकर बनाई योजनाओं में कहीं न कहीं बड़ी खामी रह गई है। स्पष्ट है कि उनके लिए बनाई गई नीतियों में संकल्पना से लेकर क्रियान्वयन तक गड़बड़ियां हैं। परिणामस्वरूप जो किसान देश का भरण-पोषण करता है वही लाचार है। हमारी आधी आबादी का फिलहाल देश की समृद्धि में केवल सातवें हिस्से का योगदान है। दूसरों के मुकाबले वे केवल 20 फीसदी कमाते हैं। भारत की 60 प्रतिशत आबादी के हिस्से में गुजर-बसर के लिए राष्ट्रीय उत्पाद का केवल सातवां हिस्सा आता है। जब आप किसानों से जमीनी स्तर पर बात करते हैं तो पाते हैं कि किसान सब्सिडी नहीं चाहते हैं। किसानों को अपने से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नगण्य होती है। इसके चलते किसान से जुड़ी योजनाओं का लाभ अक्सर बिचौलिये उठा ले जाते हैं। केवल 19 फीसद किसान सब्सिडी को जस के तस हालात में लागू रहते देखना चाहते हैं।

यूरोप इस सबक को आज काफी कड़वे ढंग से सीख रहा है जिसे लगा कि सीरिया, अफगानिस्तान और अफ्रीकी देशों की गरीबी या परेशानी से उसका कोई वास्ता नहीं है। गरीबी और असमानता केवल आर्थिक खतरा नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक खतरा भी है। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का इसकी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कायम रहे और उनका आचरण लोकतंत्र की अपेक्षा के अनुरूप रहे। गरीबी और असमानता लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से उठा देती है। नतीजा हमारी संवैधानिक संस्थाओं के साथ-साथ लोकतंत्र भी कमजोर होता है। कुछ लोग इसकी वकालत करते हैं कि खुशियों और पैसे के बीच रिश्ता नहीं है। यह बात एक जुमला ही है। हमारे शास्त्रों में ही चार पुरुषार्थों में अर्थ को मोक्ष का प्रमुख पायदान बताया गया है। समाज और कानून एवं व्यवस्था की बेहतरी के लिए सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान होना जरूरी है। व्यक्ति की गरिमा ही समाज और देश की गरिमा को सुनिश्चित करेगी। चूंकि यह बात थामस पेन जैसे दार्शनिकों ने बहुत पहले ही भांप ली थी इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15 पौंड की राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की वकालत की थी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम न तो लोगों को अकर्मण्य बनाने वाला कदम है और न ही इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। भारत से कमजोर कई मुल्कों ने राजनीतिक इच्छाशक्ति के जरिये इसे अपनाया है। मजबूत लोग ही मजबूत देश का निर्माण करते हैं। बिस्मार्क जैसे तानाशाही प्रवृत्ति वाले जर्मन राजनयिक ने इसे समझा था और सबसे पहले मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों को बनाया था। नतीजा जर्मनी कालांतर में इतनी मजबूती हासिल कर सका कि यूरोप सहित दुनिया भर में उसका सिक्का कायम हो गया।

(लेखक उद्यम एवं वित्तीय प्रबंधन मामलों के विशेषज्ञ एवं क्रक्स मैनेजमेंट सर्विसेज के संस्थापक अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### प्रार्थना

जीवन में समय-समय पर निराशा के क्षण आते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर मनुष्य विकल्पविहीन हो जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझता और अपना जीवन अंधकारमय लगने लगता है। कई बार मनोचिकित्सकों और विशेषज्ञों की राय भी उनकी निराशा का अंत नहीं कर पाती। ऐसे समय में सच्चे मन से की गई प्रार्थना मनुष्य के लिए वरदान साबित होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से मनुष्य को न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसमें जीवन को जीने का एक नया नजरिया भी विकसित होता है। प्रार्थना निराशा-अवसाद से लड़ने का एक कारगर तरीका है। प्रार्थना में मनुष्य अपने दिमाग से आगे निकलकर बाहर से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। प्रार्थना में मनुष्य अपनी गलतियों, अवगुणों और दोषों को स्वीकार करता है और सच्चे मन से प्रभु से क्षमा मांगता है। जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए ईश्वर के चरणों में क्षमा मांगता है तो ईश्वर उससे बेहद प्रसन्न होते हैं। ईश्वर न केवल उसकी पिछली गलतियों को माफ कर देते हैं, बल्कि भविष्य की राह दिखाते हुए उसे अपना आशीर्वाद भी देते हैं।

जब भी कोई व्यक्ति हताश-निराश या विचलित हो तो उसे सबसे पहले ईश्वर की सहायता लेनी चाहिए। मनुष्य की कितनी भी जटिल समस्या क्यों न हो, जब वह अपनी आंखें बंद करके ईश्वर के सम्मुख कुछ समय व्यतीत करता है तो फिर कोई भी समस्या उसे अशांत नहीं करती। हालांकि प्रार्थना में विश्वास अतिआवश्यक है, क्योंकि विश्वास से ही मनुष्य यह स्वीकारता है कि इस ब्रह्मांड में उससे भी शक्तिशाली कोई अन्य है, जिसके सामने वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर और अपने दुख-दर्द व्यक्त करके अपनी कमियों को लड़ने की शक्ति मांगता है। विश्वास से भरा मनुष्य ही जानता है कि उसके भगवान सर्वशक्तिमान हैं और वे उसके साथ अवश्य न्याय करेंगे। ईश्वर हमसे कोई मांग नहीं करता, इसलिए प्रार्थना करने का भी कोई निश्चित समय नहीं होता। ईश्वर के आगे किसी भी समय नतमस्तक हुआ जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि पूजा स्थल पर जाकर ही हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। ईश्वर को हम कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय सच्चे मन से याद कर सकते हैं।।

आचार्य अनिल वत्स

# यातना गृह बनते आश्रय घर

**मिताली जैन**

देश के विभिन्न राज्यों में बेसहारा, निराश्रित और मजबूर लोगों को सहारा देने वाले आश्रय घरों की हालत बेहद चिंतनीय है

शेल्टर होम (आश्रय घर) का नाम सुनते ही मन में गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए एक आश्रय नजर आने लगता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वही आश्रय घर लड़कियों के लिए यातना गृह में तब्दील होते जा रहे हैं। फिर चाहे बात बिहार के मुजफ्फरपुर के आश्रय घर की बात हो या पटना के आसरा आश्रय घर की। बच्चियों को असहनीय यातना देने से लेकर यौन शोषण, यहां तक कि हत्या तक सब कुछ होना जैसे इन आश्रय घरों में एक आम बात हो। अब इस सूची में दिल्ली के द्वारका स्थित एक निजी आश्रय घर का नाम भी जुड़ गया है।

इसमें छह साल से लेकर चौदह साल तक की बच्चियों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार होता है कि सुनने वाले की भी आत्मा कांप जाए। हाल ही में दिल्ली महिला आयोग के निरीक्षण के बाद इस शेल्टर होम की सच्चाई का पता चला। वहां पर अनुशासन के नाम पर लड़कियों को जबरदस्ती मिर्च खिलाई जाती थी, कंपकंपाती ठंड में सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहलाया जाता था और उनके साथ मारपीट भी की जाती थी।

देश के विभिन्न राज्यों में बेसहारा, निराश्रित और मजबूर लोगों को सहारा देने वाले इन आश्रय घरों की हालत बेहद चिंतनीय है। दूसरों के कल्याण, दया और परोपकार के नाम पर चलने वाले ये आश्रय घर वास्तव में अपराध का गढ़ बनते जा रहे हैं। इनको चलाने वाली संस्थाएं अपना हित साधने में लगी रहती हैं। इन संस्थाओं के संचालक अबोध असहाय बच्चियों को यौन सुख पाने का एक आसान जरिया समझते हैं या फिर वे अपनी कुंठा और विकृत मानसिकता के चलते इन आश्रय गृहों में रहने वाली मासूम बच्चियों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करते हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पूरे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा जोर-शोर से लिया जाता है, वहां पर इन बेटियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।

राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी इन स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपकर मुक्त हो जाती हैं। वे कभी भी यहां पर होने वाली गतिविधियों की कोई खैर-खबर नहीं लेती हैं। अगर कभी कोई मामला सामने आता भी है तो प्रशासन इन आश्रय घरों के संचालकों को दोषी बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। अब समय आ गया है कि सरकारें और समाज, दोनों ही इस बारे में नए सिरे से सोचना शुरू करें और बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर ज्यादा सजग बनें।

आखिरकार ये बेटियां भी इसी देश की हैं और अगर समाज और सरकारें उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रहती हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके लिए सबसे पहले तो न सिर्फ इस तरह की संस्थाओं पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, बल्कि उनके पंजीकरण के नियमों को भी सख्त बनाया जाना चाहिए। साथ ही देश के हर आश्रय गृह की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे हजारों आश्रय गृह होंगे, जहां पर मासूमों को असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ रही होंगी। इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं का गठन भी किया जाना चाहिए, जो इन आश्रय घरों की निगरानी करती रहें ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका होने पर जल्द कार्रवाई की जा सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### स्वच्छ राजनीति की दरकार

राजीव सचान ने अपने आलेख 'भले-बुरे का भेद मिटाती राजनीति' में वर्तमान की राजनीतिक गिरावट पर जैसी चिंता व्यक्त की है, वह सर्वथा उचित है। वस्तुतः इस देश की राजनीति में शनैः शनैः जो गिरावट आई है, उसके लिए वे क्षेत्रीय दल ही ज्यादा जिम्मेदार हैं जिन्होंने अभी तक प्रत्याशी चयन में संसद या विधानसभा की मान-मर्यादा को दरकिनार कर येन-केन-प्रकारेण केवल चुनाव जीतने को ही अपनी प्राथमिकता में रखा है। जिसके परिणाम स्वरूप साम-दाम-दंड-भेद से चुनाव जीतने में सक्षम अपराधी और माफिया भी संसद और विधानसभा की शोभा बनने लगे। चुनाव जीतने की प्रतिस्पर्धा में भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल भी इस गंदगी के शिकार हो गए। ऐसे में कुख्यात अपराधियों के लिए राजनीति अभयारण्य बन गई। अपराधी से माननीय बने इन लोगों के कारण ही राजनीति, अपराध और भ्रष्ट प्रशासन का गठजोड़ बना, जिसने सभ्य समाज के बीच भ्रष्टाचार की जड़ों को और अधिक गहरा कर दिया। इस राजनीतिक गिरावट से जहां देश को दिशा देने वाली राजनीति प्रदूषित हुई है, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज का नुकसान हुआ है। इस विकृति से बचा जा सकता है यदि राजनीति में सक्रिय लोग निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने लगें। चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में प्रत्याशी की सामाजिक छवि का विशेष खयाल रखें। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी राजनीति में स्थापित करने का काम प्रमुखता से किया जाए। आज रसातल में जाती राजनीति की भाषा और व्यवहार को मर्यादित बनाने की दृष्टि से भी यह सब किया जाना समय की मांग है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि आखिर इसकी शुरुआत करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो इसके लिए सत्ता पक्ष को ही आगे आकर विपक्ष के समक्ष स्वच्छ राजनीति का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

pandeywp1960@gmail.com

### कृषि का विकास हो

देश की 70 फीसद आबादी गांवों में रहती है और कृषि पर निर्भर है। कृषि के बिना इनका जीवन संभव नहीं है। कृषि की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देने के लिए कृषि का विकास सही ढंग से करने की जरूरत है।

अश्मिता, आंबेडकर कॉलेज

### बढ़ता प्रदूषण

देश में प्रदूषण की समस्या और बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस नए वर्ष के आगमन पर शायद ही किसी को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मालूम रहा हो। इसी के चलते कई जगह रात 12 बजते ही नए साल के आगमन पर पटाखे फोड़े गए जिससे प्रदूषण और अधिक बढ़ गया। अतः सरकार के साथ -साथ हम सभी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए एवं अपने जश्न को प्रदूषण को ध्यान में रखकर मनाना चाहिए ताकि हम एवं हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकें।

नीरज कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म

### सड़क पर छुट्टा पशु

देश में छुट्टा पशुओं की समस्या बढ़ रही है। इनके लिए चारा-पानी की भी दिक्कत है। ऐसे तमाम पशु फसलों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही हाईवे पर भी आकर बैठ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। राज्यों में जरूरत के मुताबिक गोशालाएं नहीं हैं, जो हैं उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इन पशुओं के लिए गोशालाओं की सुविधा दुरुस्त करने के साथ ही सरकार को कोई ठोस नीति बनाने की भी जरूरत है, जिससे इस समस्या का स्थाई समाधान हो सके।

चांद मोहम्मद, दिल्ली विवि

### पुलिस पर हमले

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में पुलिस पर जिस तरह से हमले हुए हैं या हो रहे हैं यह पूरे पुलिस विभाग के लिए चिंता का विषय है। साथ में प्रशासन के लिए भी बहुत गंभीर मामला है। आम आदमी के अंदर कानून को हाथ में लेने का एक फैशन सा बनता जा रहा है, यह सही नहीं है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करे।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।